

भोपाल

06 जनवरी 2024
शुक्रवार

आज का मौसम

19 अधिकतम
13 न्यूनतमअयोध्या में पुलिसकर्मी
स्मार्टफोन का उपयोग
नहीं कर सकेंगे

अयोध्या, एजेंसी। अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री पूरे विधि विधान से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। वहीं प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने अयोध्या की सुरक्षा को अभेद्य किले में बदल दिया है। इसके लिए एजेंसी इंटीलिजेंस ब्यूरो और रोड के साथ ही आईफिशियल इंटीलिजेंस की मदद भी ली जाएगी। युपी पुलिस ने अयोध्या में 22 से 26 जनवरी तक के लिए पुलिसकर्मियों के लिए आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि समारोह में इस्टर्नी देने वाले पुलिसकर्मी स्मार्ट फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। क्योंकि

फोन का इस्तेमाल करते वक्त पुलिसकर्मी इस्टर्नी पर ध्यान नहीं दे पाते। जात हो कि राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से कई खास से लेकर आम लोगों के साथ-साथ विपक्ष के कई नेताओं को न्यूता दिया गया है।

ट्रकवालों को ऑनलाइन रिपोर्ट का अधिकार मिलेगा

नई दिल्ली। देशभर में नए हिट एंड रन कानून को लेकर बवाल मचा हुआ है। नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल की। कुछ जगहों पर अपीली भी हड़ताल जारी

है। इस दौरान सड़क परिवहन मंत्रालय ने प्रस्ताव रखा है कि सड़क हादसा होने के बाद तुरंत बाद ड्राइवरों को ऑनलाइन रिपोर्ट करने की सुविधा दी जाएगी। इस प्रस्ताव का उद्देश्य भारतीय न्याय संहिता के हिट एंड रन के प्रवधानों के तहत सजा और मॉब लिंचिंग के खतरे से ड्राइवरों को बचाना है। मंत्रालय के सीधे अधिकारी ने कहा कि इस प्रस्ताव पर अखिली फैसला गृह मंत्रालय का होगा।



बेबाक खबर हर दोपहर

दोपहर मेट्रो

कोहरे का मार्च और 26 जनवरी की परेड

भोपाल समेत सम्पूर्ण मप्र में कड़ाके की ठंड, कोहरा और बरिश का दौर है। इसमें भी अगले पांच दिन राहत मिलने के आसार नहीं हैं। हीरियाणा के ऊपर वेस्टर्न डिस्टरेक्स (पश्चिमी विक्षेप) पर्किटव होने से प्रदेश में भी मौसम सर्द है। हालांकि, इस कोहरे वर्ष के बाजार 26 जनवरी पर गणतांत्रिका दिवस समारोह की परेड की रिहर्सल राजधानी के लालपरेड मैदान पर जबानी ने पूरे जोश से की। फोटो निर्मल व्यास

सीएम पहुंचे हरिद्वार, मप्र में होंगे और तबादले, मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू लोकसभा चुनाव का रंग गहराया, प्रशासनिक जमावटें तेज, चुनाव आयोग का रोल भी शुरू

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मप्र में विधानसभा चुनाव के बाद

लोकसभा चुनाव की तैयारी अपसारित व राजनीतिक स्तर पर तेज नजर आने लगी है। राज्य सरकार द्वारा मैदानी व मुख्यालय स्तर पर की जा रही अपसरों की नई पदव्यापान से बढ़ी ही अल्पतर के बीच आज से मप्र में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम भी शुरू हुआ है।

इसके तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संसाधन के लिए 22 जनवरी तक आवेदन लिए जाएंगे। माना जा रहा है कि इसके मैदान भी आज या कल में बड़े पैमाने पर तबादला सूची जारी हो सकता है, क्योंकि प्रक्रिया तेज हो जाने के बाद अपसरों की पदव्यापाना आसान नहीं होगी। सरकार नये सिरे से



मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ देहरादून एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उत्तराखण्ड के सीएम उपकुप्र सिंह धारी ने स्वागत किया।

लहराई तलवार: मुख्यमंत्री मोहन यादव के रीवा दौरे पर डिल्ली सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि यादव का रीवा से उनका एक नाता भी है, जो यहां के दामाद भी हैं। लिलिहाजा उनके स्वागत में एक अलग गो था। जात हो कि रीवा में जन आपार यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री की उनके समर्थकों ने तलवार भेंट की। इसके बाद वो रथ से ही शूरूवीं की तरह तलवार लहराने लगे।

'शिवराज के अफसरों से बदला ले रहे सीएम'



इधर मप्र काग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से बदला ले रहे हैं। जिन अधिकारियों को शिवराज ने तैनात किया था, उन्हें हटा रहे हैं। दो शाम से तभी पर्टिवारी ने यह बात कही तोकियन यह भी जोड़ा 'हालांकि कांग्रेस के इससे कोई लेनादेनी नहीं है। और ये मुख्यमंत्री का अधिकार है।' आज काग्रेस के विस चुनाव में होरे कांग्रेस उम्मीदवारों की हार पर मंथन

झांसी में कोहरे के चलते हादसा, चार मौत

झांसी एजेंसी। उत्तर प्रदेश के झांसी में घने कोहरे के बीच

सड़क हादसा हो गया, मऊरनीरु थाना क्षेत्र में दो अलग-

अलग लाइनों पर हुए हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि

आधार दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों

को अस्पताल में भर्ती

कराया गया है। एक हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने पर हुए, जिससे

मूँगफली बेचकर घर जा रहे ट्रैक्टर सवार लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर ट्रैक्टरी पलटने से एक की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। बताते हैं कि टीकमगढ़ मार्ग पर घने कोहरे के कारण चालक अचानक संतुलन छोड़ दिया।

बैठा और ट्रैक्टर पलट गया।

मूँगफली एजेंसी।

मूँगफली एजेंसी।</div

भोपाल में बारिश के साथ कड़ाके की ठंड



बूंदाबांदी की शाम...

भोपाल। राजधानी में बारिश के साथ ही कड़ाके की ठंड दस्तक दे दी है। बूंदाबांदी और बारिश का सिलसिला भोपाल में जारी रहा। पानी गिरने के कारण ही कड़ाके की सर्दी भी बढ़ गई। भोपाल में तो मानसून की तरह तेज बारिश हो चुकी है। घना कोहरा छाया रहा। इसके चलते दूर्शयता घटकर 50 मीटर से भी काम रह गई। रायसेन, सीहोर और सागर समेत कई जिलों में भी बारिश हुई है। आधे से अधिक प्रदेश में मावठा गिरने से ठिरुन बढ़ गई है।



सुबह का कोहरा

राष्ट्रीय बाल आयोग अध्यक्ष ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र, 7 दिन में रिपोर्ट मांगी बाल आयोग ने किया औचक निरीक्षण, बिना पंजीयन चल रहा था बालगृह, हुई एफआईआर

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

राष्ट्रीय बाल आयोग और मप्र बाल आयोग की टीम द्वारा बालगृहों के औचक निरीक्षण के दौरान परवलिया सड़क थाना क्षेत्र में बिना पंजीयन चलते पाए गए अंचल बालगृह के प्रबंधन के खिलाफ आयोग ने एफआईआर दर्ज करवाया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनों ने मुख्य सचिव मप्र शासन को पत्र लिखकर कार्रवाई के साथ ही 7 दिन के भीतर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय बाल आयोग अध्यक्ष ने प्रमुख सचिव से रिपोर्ट में बालगृह में रह रहे सभी नाबालिग बच्चों की आयु एवं मूल पते की जानकारी मांगी है। इसके साथ ही बालगृह में रह रहे सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर आयोग को रिपोर्ट, मप्र राज्य में स्थित ऐसे सभी बालगृह जो चाइल्डलाइन चलाने वाली संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनकी जानकारी भी मांगी है।



पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में काफी विलंब किया

आयोग के पत्र में कहा है कि निरीक्षण के दौरान बालगृह के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि बालगृह में रहने वाले बच्चों को चाइल्ड इन स्ट्रीट मिशेशन से रेस्क्यू कर बिना बाल

कल्याण समिति में प्रस्तुत किये बालगृह में रहा जा रहा है। यह बालगृह पूर्व में रेलवे चाइल्डलाइन चलाने वाली संस्था चला रहा है। आयोग के

संबंधित पुलिस ने इस प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में काफी विलंब किया। आयोग के लगातार हस्तक्षेप करने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

यह है पूरा मामला

दरअसल, बीते गुरुवार देर रात बाल आयोग की टीम द्वारा राजधानी के विभिन्न बालगृहों का औचक निरीक्षण किया गया था। इस दौरान टीम परवलिया सड़क थाना क्षेत्र स्थित अंचल बालगृह पहुंची थी। टीम को यहां में कई खामियां मिली। मामले में आयोग द्वारा मुख्य सचिव को लिखे पत्र में खुलासा हुआ है कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अंचल बालगृह न तो पंजीकृत है और न ही मान्यता प्राप्त है। बालगृह में मिली सूची में 68 निवासरत बच्चों दर्ज थी, लेकिन निरीक्षण के दौरान सिर्फ 41 बालिकाएं मौजूद थीं। वह सभी बालिकाएं बाल कल्याण समिति के आदेश के बिना रह रही हैं।

संबद्धता शुल्क बढ़ाने का विरोध कर रहे निजी कॉलेज, पुनः विचार की मांग

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

बरतकतउल्ला विश्वविद्यालय द्वारा निजी कॉलेजों के संबद्धता शुल्क में बढ़ातरी की गई है। जिसके आदेश जारी होने के बाद अब निजी कॉलेज इस बढ़ातरी का विरोध कर रहे हैं। निजी कॉलेजों ने संबद्धता शुल्क बढ़ाए जाने के विरोध में उच्च शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है और मांग की है कि सम्बद्धता शुल्क के विषय पर विवाह जारी आईडीएस

नियमानुसार पुरुष विवाह कर उचित निर्णय लिया जाए। इसके साथ ही निर्णय तक पूर्व दर से संबद्धता शुल्क लिया जाए।

इसको लेकर समस्त अशासकीय महाविद्यालय प्रबंधन संघ के अध्यक्ष ने उच्च शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा है कि बीयू द्वारा 20 जून

2023 को जारी अधिसूचना में समन्वय समिति की

100वां बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार बीयू

क्षेत्राधिकार में संचालित महाविद्यालयों की सत्र

2023-24 से संबद्धता शुल्क

विगत वर्ष की अपेक्षा 1000

प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है, जो

अनुचित एवं अवैधानिक है।

एलएलटी के लिए सत्र 2024-

23 में 2 लाख, एलएल व

बीएड के लिए तीन रुपए

एमएड के लिए तीन रुपए

संबद्धता शुल्क किया गया है। उक्त संबद्धता शुल्क

बढ़ातरी करते समय महाविद्यालयों से किसी भी

प्रकार का कोई सुझाव नहीं लिया गया है। इस प्रकार

की अनुचित एवं अवैधानिक सम्बद्धता शुल्क

बढ़ातरी से महाविद्यालय पर अधिक अर्थक बोझ

डाल दिया गया है।

संबद्धता शुल्क किया गया है। उक्त संबद्धता शुल्क

बढ़ातरी करते समय महाविद्यालयों से किसी भी

प्रकार का कोई सुझाव नहीं लिया गया है। इस प्रकार

की अनुचित एवं अवैधानिक सम्बद्धता शुल्क

बढ़ातरी से महाविद्यालय पर अधिक अर्थक बोझ

डाल दिया गया है।

संबद्धता शुल्क किया गया है। उक्त संबद्धता शुल्क

बढ़ातरी करते समय महाविद्यालयों से किसी भी

प्रकार का कोई सुझाव नहीं लिया गया है। इस प्रकार

की अनुचित एवं अवैधानिक सम्बद्धता शुल्क

बढ़ातरी से महाविद्यालय पर अधिक अर्थक बोझ

डाल दिया गया है।

सीनियर सिटीजन इलेक्ट्रिक हैमर मरीन से परेशान, कलेक्टर से जवाब-तलब

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

मप्र मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष मनोहर ममतानी ने भोपाल जिले दो मामलों में सज्जन लेते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। इलेक्ट्रिक हैमर मरीन से खुलाई होने से सीनियर सिटीजन के परेशान होने के मामले में आयोग ने कलेक्टर को जांच के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही की गई कार्यवाही के संबंध में 15 दिन में जवाब मांगा है। आयोग के दौरान टीम परवलिया सड़क थाना क्षेत्र स्थित अंचल बालगृह पहुंची थी। टीम को यहां में कई खामियां मिली। मामले में आयोग द्वारा मुख्य सचिव को लिखे पत्र में खुलासा हुआ है कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अंचल बालगृह न तो पंजीकृत है और न ही मान्यता प्राप्त है। बालगृह में मिली सूची में 68 मिलियन रुपये की निवासरत बच्चों दर्ज थी, लेकिन निरीक्षण के दौरान सिर्फ 41 बालिकाएं मौजूद थीं। वह सभी बालिकाएं बाल कल्याण समिति के आदेश के बिना रह रही हैं। जिससे वहां रहने वाले सीनियर

सिटीजन को कई परेशानियों का समाना करना पड़ रहा है। दोनों पैर फँके रहा। सीनियर सिटीजन करने स्ट्रेचर पर हूंगा थाने: भोपाल शहर के बैरागढ़ थानाक्षेत्र में अपनी एचआईआर दर्ज करने के लिये एक पीड़ित को स्ट्रेचर से आने का मामला समाप्त हो गया है। वह चलने में संभाल करने के लिये असमर्थ था। परिजन द्वारा उसे इलाज के लिये अस्पताल ले जाया गया। घटना की शिकायत करने वाले बैरागढ़ थाने में आने के लिये कहा गया। बूद थाने में आने के लिये कहा गया।

22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश की मांग

भोपाल। मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर मांग की है कि 22 जनवरी रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन मध्यप्रदेश में शासकीय कर्मचारी, अर्ध शासकीय कर्मचारी व अनियमित कर्मचारियों के लिए भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए ताकि कर्मचारी राम की प्राणप्रतिष्ठा में शामिल हो सके। कर्मचारी मंच भी 10 जनवरी से एक दीप राम के नाम अभियान चलाएगा।

परंपरा, आदर्शों व जीवन मूल्यों से जुड़ना आवश्यक: प्रो.त्रिपाठी



भोपाल। हमें अपनी पंजाब, आदर्शों व जीवन मूल्यों से जुड़ा आवश्यक है। मानवीय मू

गिद्धों की गणना की तैयारी पूरी, अब घड़ियाल भी गिने जाएंगे

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

प्रदेश में गिद्धों की गणना की तैयारी पूरी हो गई है। यह गिनती फरवरी के शुरुआत में होगी। इसी माह चबल अभ्यारण में घड़ियालों की गिनती भी होगी। इस बार गिद्ध और घड़ियालों की गिनती में ज्यादा सावधानी बरती जानी है ताकि शत-प्रतिशत गिद्ध और घड़ियालों को गिना जा सके। असल में मप्र में



9000 से अधिक अधिक गिद्ध हैं, ये करीब 1800 से अधिक स्थानों पर पाए जाते हैं। बीते एक साल से इनकी संख्या के और बढ़ने के अनुमान हैं। कुछ हड्डे साइट भी मिली हैं, जहां गिद्धों की मौजूदगी है। प्रदेश के सभी बन मंडल, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्कों में अमले की प्रशिक्षित भरवाई करना मुश्किल हो रहा है।

किया जा रहा है। उधर घड़ियाल अभ्यारण में भी अमले को प्रशिक्षित किया जा रहा है। हालांकि यह बन विभाग के पास एक नया सकट यह है कि कई प्रशिक्षित बनकर्मी बीते एक वर्ष में रिटायर्ड हुए हैं, जो कि वर्षों से घड़ियाल गिनती में अहम योगदान दे रहे थे। अब अधिकारियों के लिए ऐसे अमले की भरवाई करना मुश्किल हो रहा है।



नाकेदारों को नई सरकार से न्याय की उम्मीद

प्रदेश के अलग-अलग जिलों में नाकेदारों को मिल रहा अलग वेतन

भोपाल, दोपहर मेट्रो। प्रदेश के हजारों नाकेदारों को नई सरकार से न्याय की उम्मीद है। ये वेतन में किए जा रहे भेदभाव से परेशान हैं। कुछ नाकेदारों को नियम के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है तो कुछ को नियम से कम भुगतान हो रहा है। जिसके कारण ये खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यह स्थिति पिछले कई सालों से बड़ी हुई है। वर्तान में भोपाल समेत आसपास के जिलों के हजारों नाकेदारों को कम वेतन मिल रहा है, जबकि इनसे बाद में सेवा में आए नाकेदारों को जबलपुर, सागर, सिवनी में अधिक वेतन मिल रहा है।

48 हजार स्थाईकर्मी चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा से वंचित, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर की मांग

भोपाल। स्थाई कर्मियों को भी उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में शासकीय चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ देने से करीब 48 हजार स्थाई कर्मियों को लाभ मिल सकता है। यह बात कर्मचारी मंच के अध्यक्ष अशोक पांडे ने कही है कि और मुख्यमंत्री को इस आशय का ज्ञापन दिया है। इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय जबलपुर ने अपने एक आदेश में निर्णय दिया है कि प्रदेश सरकार की शासकीय नियमित कर्मचारी ही नहीं प्रदेश के अनियमित स्थाई कर्मियों को भी परिवार सहित चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ दिया जाए। खंडपाट के जरिये विनय सराफ़ ने बीज विकास नियम के कर्मचारी आनंद बारी की याचिका में आदेश दिया कि सिविल सर्विस (मेडिकल सेवा) नियम 1998 की कांडिका(1/2) में प्रावधान है कर्मचारी याहे वह सेवा में हो प्रति नियुक्ति पर हो आकाश पर या निलंबित हो उन्हें चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ दिया जाना चाहिए। बनरक्षकों ने किया जागरार - इसर, देवेभी कर्मचारी से बनरक्षक पर पर नियमित हुए बनरक्षकों ने पदोन्नति एवं पुरानी पेंशन योजना के लाभ के लिए सेवा की वरिष्ठता देने की मांग को लेकर इंदिरा नियुक्त नर्सरी से जन जागरार शुरू किया है। इसके तहत मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया। बताया जाता है कि देवेभी से बनरक्षक पद पर नियमित कर्मचारियों को नियुक्ति के 16 साल बाद भी यह सुविधा नहीं दी गई है।

कॉलेजों, जिला मुख्यालयों में उच्च शिक्षा मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन छात्रवृत्ति पोर्टल शुरू कराने अभाविप ने प्रदेशभर में किया विरोध प्रदर्शन



भोपाल, दोपहर मेट्रो।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्रवृत्ति के सभी पोर्टल जल्द प्रारंभ कराने के लिए शुक्रवार के प्रदेशभर के कालेजों और जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अभाविप की

शास्त्रीय मंत्री शालिनी वर्मा ने कहा कि प्रदेश के डेढ़ लाख से अधिक विद्यार्थी आज छात्रवृत्ति संबंधी विभिन्न प्रकार की योजनाएं बंद होने के कारण प्रभावित हो रहा है। विगत 6 महीने से छात्रवृत्ति का पोर्टल रुपरूप होने के कारण इसकी पोर्टल रुपरूप करने की विद्यार्थियों को पोस्टमेट्रिक

छात्रवृत्ति, आवास, गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। विद्यार्थियों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उच्च शिक्षा विभाग छात्रवृत्ति में निर्णय करने के लिए विभिन्न प्राध्यापक संघ के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर कैलश त्यागी के नेतृत्व में प्राध्यापक संघ के पदाधिकारियों ने उच्च शिक्षा मंत्री के आवास कार्यालय पहुंचकर उन्हें नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर संघ की ओर से विलंबित योगी के सन्दर्भ में एक ज्ञापन सौंपा गया।

मेट्रो एंकर

जनवरी सरकार की, फरवरी से हिसाब मांगेंगी कांग्रेस

पटवारी ने कहा- वादे पूरे नहीं कर रही भाजपा

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

मप्र कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि लोकतंत्र में जिसे ज्यादा मत मिलता है, वह जीता है। हम चुनाव परिणाम को सिर माथे पर लेते हैं पर जनवरी भाजपा सरकार की है और जनवरी के बाद कांग्रेस पार्टी विकास की जिम्मेदारी निभाएगी और एक-एक घोषणा पर हिसाब लेंगी। पटवारी ने जबलपुर में मीडिया

योजना में बहनों को 3000 रु. प्रति माह दिए जाएंगे,

किसानों से 3100 रु. प्रति क्लिंटल धन और 2700 रुपए प्रति क्लिंटल के रेट से गेहूं की खरीद की जाएगी, इसके अलावा रसोई गैस का पिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा। लेकिन चुनाव पराएँ तो एक महीना हो चुका है। अब तक सरकार ने कोई भी वादा नहीं निभाया है। विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री ने भाजपा का वचन पत्र हाथ में लेकर कहा

कि यह हमारी रामायण और गीता है तो मैं जाना

चाहता हूं कि दो-तीन दिन पहले जबलपुर में कैविनेट की जो बैठक हुई उसमें इस रामायण और गीता का एक भी वचन पूरा करने का फैसला किया नहीं लिया गया। पटवारी ने कहा कि जबलपुर कैविनेट बैठक के दिन ही खबर आई थी कि सरकार जनवरी से लेकर मार्च के बीच में 28,500

दोपहर मेट्रो

अपने कारोबार-उत्पाद को आगे बढ़ाएं दोपहर मेट्रो के साथ



विज्ञापनों के लिए संपर्क करें
प्रधान कार्यालय 182 - ए शाहपुरा (मनीषा मार्केट के पास) भोपाल
फोन नं.- 0755-4917524, 0755-2972022



सुविचार

“दिल पर हरणिज ना लौजिये अगर कोई आपको बुरा कहे,
कायनात में ऐसा कोई है ही नहीं जिसे हर शख्स अच्छा कहे।”

- अज्ञात

I am kndh;

ईमानदारी के दावे और जांच

देश के दो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व अरविंद केरीबाल इन दिनों जांच एजेंसी ईंडी के बजूद को लगभग नकारते नजर आ रहे हैं। इसके राजनीतिक कारण भी हैं और कुछ इस एजेंसी का अत्यधिक सक्रिय होना तथा गैर भाजपाई नेताओं पर टूट पड़ना भी है। हालांकि जब भी किसी राजनेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो वह संविधित जांच एजेंसी को ही कठघरे में खड़ा करने लगता है। अगर संविधित राजनेता किसी राज्य की कमान संभाले हाए हो तो वह अपने पक्ष में पूरे तंत्र को खड़ा कर देता है। दिल्ली और झारखण्ड के मुख्यमंत्री यहीं पैंतीरा आजमा रहे हैं। अवैध खनन में धनशोधन मामले की जांच के सालसिले में पूछताल के लिए प्रवर्तन निदेशालय के झारखण्ड के सीएम सैरेन उसमें सहयोग करने से बचते रहे हैं। उन्होंने पार्टी, विधायकों और मंत्रियों की बैठक बुला कर समर्थन हासिल कर लिया है कि अगर प्रवर्तन निदेशालय उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है, तो भी वही मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। यही कवायद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केरीबाल कर चुके हैं। उन पर कथित दिल्ली शराब घोटाले में सहयोग करने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय उन्हें तीन बार पूछताल के लिए बुला चुका है, मगर वे उसके नोटिस को ही प्रस्तुतीकृत कर चुके हैं। वे और उनकी पार्टी लगातार इसके पीछे केंद्र सरकार की गलत मंशा बताते रहे हैं। नियम कायदे से आरोपी को जांच एजेंसियों के सवालों का जवाब देकर सांचित करना होता है कि वह निरपराध है। गैरतलत है कि स्टर एसेलालय लंबे समय से दिल्ली शराब घोटाले और झारखण्ड में अवैध खनन से जुड़े मामलों की जांच कर रहा है। उसे कुछ तो तथ्य हाथ लगे होंगे, जिनके आधार पर उसने दोनों मुख्यमंत्रियों को पूछताल के लिए तलब किया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी कहते रहे थे कि शराब घोटाले में उनका कोई हाथ नहीं है, मगर प्रवर्तन निदेशालय के सवालों पर वे अपने बचाव में उचित तथ्य पेश नहीं कर सके। अब बेशक आम आदमी पार्टी उन्हें बेक्सू और साजिश के तहत फंसाया गया बता रही हो, पर अदालत ने भी माना है कि वे संदेह के दायरे से बाहर नहीं हैं। इसलिए मुख्यमंत्री अरविंद केरीबाल के इस तक में कोई दम नजर नहीं आता कि केंद्र सरकार उन्हें जेल भेजना चाहती है। जब तक ईंडी के आरोपों के तात्पर्य के जरिए बेबुनियाद नहीं ठहरा देते, वे सवालों के धोरे में बन रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री से इसलिए भी सवालों का सामना करने की अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी पार्टी के गठन के दिन से ही दाव करते नहीं थकते कि उनकी पार्टी कट्टर ईमानदार है। ईमानदारी का प्रमाण इसका जुबानी एलान नहीं हो सकता। उसे सवालों के साथ पेश करना पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली सरकार के अनेक फैसले और योजनाएं अनियमिताओं के आरोप झेल रही हैं। मुख्यमंत्री और उनके मंत्री दावा करते हैं कि हर काम उन्होंने पारदर्शी तरीके से किया है। अगर ऐसा है तो जांच से भागने की जरूरत क्या है। जनहित से जुड़े मामलों में लगे भ्रष्टाचार के आरोप राजनीतिक रंग दे देने से समाप्त नहीं हो जाते। बात फिर घमंपकर वहीं आती है कि जांच एजेंसियों की विपक्षी दली के नेताओं के मामले में फैरन ?सक्रियता उसके कामकाज के तरीके सवाल लगती है। पिछले कुछ वर्षों में कई गंभीर सवाल उठे भी हैं, पर सैरेन और केरीबाल इससे बचे बिना कैसे खुद को पाक साफ साखित कर सकते।

देविंदर शर्मा

यदि आजादी के 76 साल बाद भी, 74 फीसदी से भी अधिक भारतीय स्वास्थ्यवर्धक भोजन का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है तो कुछ तो है जो गलत हो रहा है। यह भी तब जबकि देश दुनिया की सबसे तेज गति से तरकी कर रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और संवृद्धि दर अनुमानों के लिहाज से जिन्हें यह लगभग हासिल कर ही लगा, लगभग 2027 तक भारत के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। अर्थव्यवस्था का आकार जो भी हो, और वह भी अधिकांश अस्वस्थ आबादी से निर्मित हो तो वह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ग्रोथ मैट्रिक्स यानी संवृद्धि का सांचा देश के स्वास्थ्य से मेल नहीं खाता है।

यह निश्चित तौर पर चिंताजनक है। जब प्रधानमंत्री नेंद्र मोदी ने ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ की अवधि पांच साल और बढ़ाने की घोषणा की, जिसके तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन मिलाना जारी रहेगा, तो इससे पूरी तरह स्पष्ट था कि सरकार ने जरूरत समझी है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत निर्धारित 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत पर सब्सिडी वाले खाद्यान्न, जिसके हक्कदार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, के अलावा 5 किलोग्राम मुफ्त राशन भी दिया जाये। क्योंकि एनएफएसए आबादी के 67 प्रतिशत हिस्से को जरूरत पूरी करता है, इसके साथ ही अन्य 10 फीसदी भाग ऐसा है जिसके खुरक के स्तर को बेहतर बनाने की तुरंत जरूरत है। युवत राशन खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) ने अपने खाद्य सुरक्षा और पोषण के क्षेत्रीय अवलोकन 2023 में ये हैरान कर देने वाले आंकड़े उत्तरांग किये।

यह वर्ष 2021 के लिए अनुमानों पर आधारित था, जो महामारी का साल था, परंतु अध्ययन बताता है कि क्षेत्र का उसी तरह के प्रभावों के फैलाव से ग्रस्त रहना जारी है। निराशाजनक रूप से, रिपोर्ट बताती है कि एशिया-प्रश्ट्रिय क्षेत्र में पोषण के लिहाज से 37.07 करोड़ गरीब लोग मोर्जू हैं जो वैशिक्षक स्तर पर कुपोषित जनसंख्या के आधे से ज्यादा है। भारत के अलावा पाकिस्तान में 82.8 प्रतिशत और 45.2 प्रतिशत जनसंख्या कुपोषण से ग्रस्त हैं। इस तरह से दक्षिण एशियाई क्षेत्र वैशिक्षक अत्यपोषित मानचित्र पर हावी है।

एफएओ की रिपोर्ट यह भी बताती है कि देश की 53 प्रतिशत महिलाओं में रक्ताल्पता की समस्या है, और पांच साल से कम आयु के 31.7 फीसदी बच्चों की हाईट उम्र के लिहाज से कम है, इसके साथ ही 18.7 प्रतिशत बच्चों का बजन तकनीकी तौर पर उनकी ऊंचाई के अनुरूप कम है। रोक बात यह है कि यही अनुमान पूर्व में वैशिक्षक भूख

तरक्की के आंकड़ों संग सुधरे देश की सेहत



सूचकांक (जीएचआई) में चिह्नित किये गये थे जिन्हें भारत ने यह कहकर नकार दिया था कि इनके लिए अपनी गयी कार्यप्रणाली सही नहीं है। जबकि एफएओ का कहना है कि जब तक बढ़ रही आय का स्तर बढ़ रही खाद्य कीमतों के बाबर नहीं होती है, अस्वास्थ्यकर भोजन की प्रवृत्ति घटेगी नहीं। जहां तक आय स्तर का संबंध है तो भारत की अधिकांश जनसंख्या लगातार उस स्तर पर है जो सब-संसार का मानक में मौजूद है। देश के एक अंग्रेजी कॉम्पनी समाचारपत्र में 10 अगस्त, 2022 में प्रकाशित लेख ‘फोकस ऑन द बैंक्स और ए प्रिपाइड’ में ये अनुमान था कि 90 करोड़ भारतीय उन्हीं ही आय में निवाह कर रहे थे जिन्हीं आमदार सब सहराय अक्षीका में हैं। इन्हें इसका जेपाल में 76.4 फीसदी, ग्रीनलैंड में 55.2 फीसदी और भूटान में 45.2 प्रतिशत जनसंख्या कुपोषण से ग्रस्त है। इस तरह से दक्षिण एशियाई क्षेत्र वैशिक्षक अत्यपोषित है।

एफएओ की रिपोर्ट यह भी बताती है कि देश की 53 प्रतिशत महिलाओं में रक्ताल्पता की समस्या है, और पांच साल से कम आयु के 31.7 फीसदी बच्चों की हाईट उम्र के लिहाज से कम है, इसके साथ ही 18.7 प्रतिशत बच्चों का बजन तकनीकी तौर पर उनकी ऊंचाई के अनुरूप कम है। रोक बात यह है कि यही अनुमान पूर्व में वैशिक्षक भूख

आय स्तर पर 51 प्रतिशत आबादी के साथ दक्षिण अफ्रीका दूसरे स्थान पर आता था।

स्वास्थ्यकर खुरक प्राप्त करने को लेकर, जबाब यही है कि पिपाइड की सहत पर प्रचलित आय स्तर को बढ़ाया जाये। यह मुश्किल लगाता है, और कुछ तो इसे असंभव हो कहोंगे, पर हक्कदार के अधिकांश जनसंख्या लगातार उस स्तर पर है जो सब-संसार का मानक में मौजूद है। देश के एक अंग्रेजी कॉम्पनी समाचारपत्र में 10 अगस्त, 2022 में प्रकाशित लेख ‘फोकस ऑन द बैंक्स और ए प्रिपाइड’ में ये अनुमान था कि 90 करोड़ भारतीय उन्हीं ही आय में निवाह कर रहे थे जिन्हीं आमदार सब सहराय अक्षीका में हैं। इन्हें इसका जेपाल में 76.4 फीसदी, ग्रीनलैंड में 55.2 फीसदी और भूटान में 45.2 प्रतिशत जनसंख्या कुपोषण से ग्रस्त है। इस तरह से दक्षिण एशियाई क्षेत्र वैशिक्षक अत्यपोषित है।

महांगां नियंत्रण के मकसद से कृषि क्षेत्र को जानबूझकर दिव्य बनाये रखने के चलते मैंनें इनकी नीतियों ने कृषि को व्यवहार्य

विकल्प बनाने के प्रयासों को दबा दिया है। यह मुझे राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर एक त्रुटीपूर्ण ग्रथ की याद दिलाता है जिसे नौती आयोग ने साल 2020 में देशभर में एक आम आदमी द्वारा भुगतान की जाने वाले भोजन (थाली) की लागत को मापने के मकसद से तैयार किया था। दिल्ली में 8 फरवरी, 2020 को प्रकाशित मेरे एक लेख ‘शाली इकोनॉमिक्स गेट्स इट रॉन’ में मैंने व्याख्या की है कि कैसे थाली इकोनॉमिक्स, जैसा कि इसे कहा गया, केवल यह सेवा देने के लिए थी कि खाद्य कीमतों एक औसत आदमी की पहुंच में हैं। असल में, रिपोर्ट में यह बात चुनौती से हुआ तो वायदा थी कि सर्वतों ने दिल्ली के ल

नए कलेक्टर ने संभाला कामकाज

भोपाल, दोपहर मेट्रो

कलेक्टर आशीष सिंह का आठ महीने के कार्यकारी बाट ही उनको कलेक्टर इंदौर बनाने की वजह से उनको जगह वर्ष 2010 बैच के आईएस अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने भोपाल कलेक्टर का पद संभाल लिया। बता दें कि आठ महीने पहले अंतिम 2023 में भी कौशलेंद्र विक्रम सिंह को भोपाल कलेक्टर बनाया गया था लेकिन बाद में उनको मध्यप्रदेश विकास निगम के एमडी की जिम्मेदारी सौंप दी थी। सिंह मूलतः हरदौड़, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वह पूर्व में



व्यालियर कलेक्टर के पद पर कार्यरत थे, इसके बाद उनका तबादला करते हुए उन्हें अपर सचिव, मुख्यमंत्री एवं अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्टन विकास निगम भोपाल पर्टन में भ्रमण किया गया था। उन्होंने प्रभार पदस्थ किया गया था। उन्होंने लंबे समय तक व्यालियर में कलेक्टर का कार्यभार संभाला था,

वह काग्रेस और भाजपा दोनों के सम्पर्क कार्यरत रहे।

उन्होंने दिव्यांगों को राशन देने के लिए मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना की शुरूआत की थी, जिसकी खुद संचालक, मध्यप्रदेश पर्टन विकास निगम सिंह ने सरहना की थी। उन्होंने लंबे समय तक व्यालियर में एकसीरियें अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है।

वारदात के समय पूरा परिवार शहर से बाहर गया हुआ था।

कोहफिजा में दिनदहाड़े प्लैट का ताला तोड़कर जेवर-नकदी चोरी

भोपाल, दोपहर मेट्रो

कोहफिजा में एक प्लैट का ताला तोड़कर चोरी कर ले गए। वारदात के समय पूरा परिवार शहर से बाहर गया हुआ था। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।



पुलिस के मुताबिक दीपक पुरोहित (45) सिंहर्डी अपार्टमेंट कोहफिजा में रहते हैं और मीडिया हाउस के एकाउंट विभाग में काम करते हैं। वीती 28 दिसंबर को वह अपने पर्सैट पर ताला लाकर परिवार समेत मनाली चले गए थे। गुरुवार को वापस लौटे तो पर्सैट का ताला खुला मिला। अंदर जाकर देखा तो भीतर वाले कमरे का सामान खिलाफा पड़ा था और अलमारी में रुपये सोने के टाप्स तथा 15 हजार रुपये नकदी गयबक थे। दीपक ने पुलिस को बताया कि बदमाशों ने दिन के समय प्लैट का ताला तोड़कर उत्तर वारदात को अंजाम दिया है, क्योंकि रात के समय अपार्टमेंट के चैनल गेट पर ताला लगा दिया जाता है।

पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इसी थानांतर्गत राशी अपार्टमेंट विजय नगर लालचाटी में रहने वाले आशीष सराकर के बाइक चोरी हो गई। पुलिस ने बताया कि आशीष लखेरापुरा के कपड़े का व्यवसाय करते हैं। वीती 20 दिसंबर को उन्होंने पाकिंग में अपनी बाइक खड़ी की ओर पर्सैट में चले गए। आले दिन सुबह देखा तो बाइक चोरी हो चुकी थी। कई दिनों तक तलाश करने के बाद भी जब बाइक का कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने गुरुवार को थाने जाकर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

पाकिंग में अपनी बाइक खड़ी की ओर पर्सैट में चले गए। आले दिन सुबह देखा तो बाइक चोरी हो चुकी थी। कई दिनों तक तलाश करने के बाद भी जब बाइक का कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने गुरुवार को थाने जाकर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पत्नी और बेटे से हुआ था विवाद

भोपाल। कमला नगर थाना क्षेत्र स्थित नया बसरा, कोरा सुल्तानाबाद में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत से पहले उसका पती और जवान बेटे से विवाद हुआ था। पुलिस ने मर्ग कायम कर शब्द पीएम के बाद परिजन को सौंप दिया है। पुलिस पीएम रिपोर्ट मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

पुलिस के अनुसार, श्वेतजीत सहरिया (42) यहां नया बसरा कोटरा में रहता था और दवाइयों की मार्केटिंग करता था। उसकी पती अलग राजस्थान में रहती है और प्रायवेट काम करती है, जबकि बेटा भोपाल में ही रहता है। शुक्रवार को पती और बेटा स्वेतजीत के घर पहुंचे थे, जहां पारिवारिक बात को लेकर उनके बीच विवाद हो गया। इसके बाद स्वेतजीत बेंसुध होकर घर में ही गिर पड़ी। उन्हें इलाज के लिए जयप्रकाश अस्पताल ले जाया गया, वहां डॉक्टर ने प्राथमिक जांच में ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि स्वेतजीत को हाँसंबंधी समस्या थी और उनका आपरेशन हो चुका था।

गुनगा में युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी

भोपाल। गुनगा इलाके में रहने वाले एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक अजय कुशवाह पुत्र श्यामलाल कुशवाह (24) ग्राम कलारा में रहता था और मजदूरी करता था। वह काम पर जाने का कहकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। शुक्रवार दोपहर को परिजन खेत पर पहुंचे तो एक पेड़ पर उसकी लाश लटकी मिली। पुलिस ने मर्ग कायम कर शब्द पीएम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार कुमारी

डीआईजी ने दिए छात्रों को परीक्षा के टिप्प

भोपाल, दोपहर मेट्रो

पुलिस परिवार के बच्चों के लिए पुलिस पब्लिक स्कूल दिशा अध्ययन केंद्र में करियर कार्यसलिंग सेमिनार का आयोजन किया गया। इस आयोजन में डीआईजी विनियत कपूर द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों को उत्जवल भविष्य की तैयारी कर रहे बच्चों से परिचय लिया

और परिवार में पारिवारिक जानकारी प्राप्त की। बच्चे किस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यह भी जानकारी ली। इसके साथ ही दिशा अध्ययन केंद्र में एमपीपीएससी, एसएसपी, बैंक से संबंधित विषयों की परीक्षा आदि की तैयारी कर रहे बच्चों को उत्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने बच्चों से परिचय लिया

में स्लेबस ऑपसन एलिमेनेशन पर चर्चा करते हुए बच्चों मार्गदर्शन दिया। बच्चों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब एवं उनकी समस्याओं का सिरकरण भी श्री कपूर ने किया। इस के बाद एसबीआई बैंक से आए सीनियर मैनेजर अनिल चौबे एवं विकास मिश्रा ने बैंक जांच के बारे में बच्चों को जानकारी दी।

शादी का ज्ञांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण

भोपाल। कमला नगर थाना को एक युवती की रिपोर्ट पर परिचित युवक के खिलाफ शादी का ज्ञांसा देकर शारीरिक शोषण करने का मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक 28 वर्षीय युवत बैतूल की रहने वाली है। वीती 28 दिसंबर को युवती एमपीएस के पढ़ाई के लिए भोपाल आई तो मुकेश का उत्तरके यहां आना-जाना हो गया। इस दौरान मुकेश ने शादी को ज्ञांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण किया। युवती ने जब शादी के लिए दबाव डाला तो उसने इंकार कर दिया। परेशान होकर पीड़िता ने उसे जाकर मुकेश के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। इस रातीबद्ध पुलिस ने बीस वर्षीय युवती की रिपोर्ट पर नाजिम नामक युवक के खिलाफ डेंड्राइड का केस दर्ज किया है।



कोटों प्रोत्साहन देने के लिए डीआईजी लाइन से एसीपी अंकिता खातारकर ने प्रशिक्षण

स्थल पर पहुंचकर महिलाओं को अधिक से अधिक इस कार्यक्रम में जुड़ने की अपील की।

मेट्रो एंकर साइबर इनेबल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर सेमिनार

साइबर अपराधियों से निपटने जागरूकता जरूरी

भोपाल, दोपहर मेट्रो



महिलाएं और बच्चे ही नहीं, पुरुष भी मानव दुव्यापर के शिकार

प्रज्ञवला की प्रोजेक्ट एडवाइजर डॉ. सुनीथा कृष्णन ने कहा कि तकनीक का उपयोग कर मानव दुव्यापर में लिप्स आपीपी, पीडित को गुपराह कर अपने ज्ञांसे में फंसाते हैं या लालच देकर उन्हें शोषण की ओर धकेला जाता है। यह केवल महिलाओं और बच्चों के साथ नहीं बल्कि पुरुष वर्ग भी हो रहा है। पहले यह माना जाता था कि केवल गरीब, अशिक्षित, विशेष समृद्धयाकार या जाति के लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं। चिंता का विषय यह है कि हमारे बच्चे भी इसका शिकार बन रहे हैं। उन्हें ऑनलाइन गेमिंग और वेबसाइट्स के माध्यम से सेक्सस्टोरिंग की ओर धकेला जा रहा है।

कोरोना के बाद अचानक बढ़े मामले

प्रज्ञवला टीम की प्रोजेक्ट क्राइमिनेट स्टरिस राणा ने कहा कि मानव दुव्यापर के लिए तकनीक का उपयोग अधिक बढ़ा है। दरअसल ऑनलाइन व्हालसेस के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल पहुंच गया, जिसका फायदा उठाकर मानव दुव्यापर करने वाले ने बच्चों को शिकार बनाना शुरू किया। हमारी संस्का 11 ज्ञांसों में शोष कर रही है, जिसके बाद सकार के साथ मिलकर मानव दुव्यापर रोकने में नेशनल एक्शन प्लान बनाने में मदद मिलेगी।

अकेलापन महसूस करने वाली महिलाएं रहती हैं टारगेट

प्रिसर्च ऑफिस